

न्यायालय संगणनीय आयुक्त, बीकानेर संगणना, बीकानेर
पीठाधीन अधिकारी श्री भूवर लाल मेहरा, आर्.ए.एस.

अपील संख्या : 14/2017 शस्त्र अधिनियम

अनवानी :- नवदीपसिंह पुत्र श्री बलवंतसिंह जाति जटसिंह निवासी करडवाला
तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

-----अपीलान्त

-----बनाम-----

राजस्थान राज्य ।

-----रेस्पोडेन्ट

उपरिष्ठत :- श्री ज्ञानसिंह बिस्नोई

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़

सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की

ओर से ।

निर्णय

दिनांक : 28.06.2021

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.03.2017, जिसमें अपीलान्त द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने अपने नाम से नवीन शस्त्र

अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष

दिनांक 19.01.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक,

श्रीगंगानगर, से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर

की रिपोर्ट क्रमांक 1124 दिनांक 24.3.17 में आवेदक के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं

करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही पाये गये हैं।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलान्त आदेश दिनांक 30.3.2017 में उल्लेख

किया है कि आवेदक द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा

प्रार्थी वर्तमान में राजकीय सेवा में जल प्रहरी के पद पर केन्द्रीय कारगारह,

हनुमानगढ में पदस्थानित है। उसे किसी प्रकार से जानमाल का खतरा नहीं है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्म्स नियम 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त

उपनियमों की पूर्ति नहीं करता है। इसी आधार पर अपीलान्त का आवेदन पत्र

अपीलान्त आदेश दिनांक 30.3.2017 से निरस्त कर दिया, जिससे अपीलान्त होकर

यह अपील प्रस्तुत हुई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिपोर्ट तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी।
4. विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ श्री ज्ञानसिंह बिस्नोई ने बहस में मुख्यतः कथन किया है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में अधीनस्थ के विरुद्ध किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अधीनस्थ के विरुद्ध कहीं पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थीन आदेश में लिये गये आधार बर्णित है। अधीनस्थ आदेश में राज्य नियम 2016 के नियम 11 में राज्य अनुज्ञा पत्र के लिये आवेदन करने का तरीका बताया गया है तथा उपनियम 4 में आवेदन पत्र के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेजों का बतलाया है। इस नियम 11 में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के बारे में नहीं बताया गया है, ना ही प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का परफॉर्मा अभी लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय में प्रहरी के पद पर तैनात है। अधीनस्थ ने आत्म रक्षाई राज्य अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन किया था। इन समस्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय राज्य नियम 2016 के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अधीनस्थ अधीनस्थ स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।
5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री गजेंद्रसिंह रावैड ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ ने राज्य अधिनियम 2016 में विद्यमान प्राधान्यों के अनुक्रम आवेदन नहीं किया है। राज्य नियम 11 एवं 12 एवं समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं की गई है। अधीनस्थ ने राज्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का अधीनस्थीन आदेश उचित है। अतः अधीनस्थ अधीनस्थ निरस्त करमाई जावे।
6. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ की बहस में मुख्य कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1124 दिनांक 24.03.2017 में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। इस रिपोर्ट में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही पाये जाने का उल्लेख किया है। अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय में पदस्थानित है। अधीनस्थ के

श्रीकांनर
संमगीय आरुत
(शर लल शर)

न्यायालय में सुनाया गया।

8. तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्मित शंमार होकर नम्बर से कम हो तथा मिसल बाद तर्तीब तकमील दखिल दफतर हो। आदेश आज दिनांक 28.06.2021 को खुले

7. उपरोक्त तथ्यों को मखनजर रखते हुए हम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलान्ट आदेश दिनांक 30.03.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलान्ट आदेश दिनांक 30.03.2017 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं।
वाहिये, परन्तु उसने जान-माल का खतरा होने का कोई युक्तिरुक्त कथन या साक्ष्य भी हमारे समक्ष पेश नहीं किये गये हैं। अपीलान्ट को आत्मरक्षा शस्त्र आवश्यक है। वरवक्त बहस आवेक द्वारा शस्त्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या अन्य कोई प्रमाण पत्र भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि 12 एवं समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं की गई है। अपीलान्ट ने शस्त्र प्रशिक्षण 2016 में विद्यमान प्रावधानों के अनुरूप आवेदन नहीं किया है। शस्त्र नियम 11 एवं लोक अभियोजक के इस कथन से हम सहमत हैं कि अपीलान्ट ने शस्त्र अधिनियम आदेश में लिये गये आधारों को अर्जित बताया है। राज्य पक्ष की ओर से सहायक अधिनियम 2016 के नियम 11 उपनियम 4 एवं अधिनस्थ न्यायालय के अपीलान्ट के अपीलान्ट को अपनी सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यक होना बताया। शस्त्र विच्छेद किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण विचारणीय या दर्ज नहीं हुआ है।